The Achievers IAS Academy

Patliputra colony, Near: Tennis Court; Patna. Contact: 8434931877, 7250667974

1. बिहार में इथनॉल उत्पादन

- मधुबनी, मोतिहारी और गोपालगंज में इथनॉल उत्पादन इकाई स्थापित किए जाने के तीन प्रस्तावों को पहले स्टेज में मंजूरी मिल चुकी है। निवेश प्रस्तावों से बिहार में करीब 650 करोड़ का इंवेस्ट होने की उम्मीद है।
- केंद्र द्वारा बिना चीनी के सीधे इथनॉल बनाए जाने संबंधी नियमों में बदलाव के बाद राज्य कैबिनेट ने नई इथनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2007 में ही तत्कालीन केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था।
- बिहार अलग इथनॉल नीति लाने वाला देश का पहला राज्य है। पिछले दिनों नई नीति को जारी करते हुए उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बिहार को इथनॉल हब बनाने की बात कही थी। राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद ने जिन प्रस्तावों को पहले चरण की मंजूरी दी है, उसमें सबसे प्रमुख मिथिलांचल क्षेत्र के मधुबनी जिले का है।

मधुबनी के लोहट में सबसे बड़ा प्रस्ताव

- कभी चीनी उत्पादन (Sugar Production) के लिए पहचान रखने वाले मिथिलांचल में अब इथनॉल भी बनेगा। मधुबनी के लोहट में कभी चीनी मिल हुआ करती थी। अब वहां सोनासती ऑर्गेनिक्स के इथनॉल इकाई स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। कंपनी यहां इथनॉल के अलावा चीनी और बिजली भी बनाएगी। इसमें करीब 400 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है।
- मोतिहारी और गोपालगंज में भी इथनॉल उत्पादन इकाइयों को मंजूरी दी गई है। इनमें 250 करोड़ से अधिक का निवेश होगा। मोतिहारी में तिरहुत उद्योग प्राइवेट लिमिटेड ने 120 करोड़ की लागत से इथनॉल प्लांट लगाने का प्रस्ताव दिया है। वहीं, गोपालगंज में भारत सुगर मिल भी इथनॉल उत्पादन शुरू करेगा। कंपनी ने 133 करोड़ का निवेश प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया है।

देश के लिए इथनॉल क्यों जरूरी है?

- इथनॉल एक तरह का अल्कोहल है, जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इथनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने की फसल से होती है, लेकिन मिठास वाली कई दूसरे फसलों से भी इसे तैयार किया जा सकता है। इथनॉल के इस्तेमाल से 35 फीसदी कम कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होता है। इतना ही नहीं यह कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन और सल्फर डाइऑक्साइड को भी कम करता है। इसके अलावा इथनॉल हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन को भी कम करता है। इथनॉल में 35 फीसदी ऑक्सीजन होता है।

2. खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोइंग डिसिप्लिन (discipline).

- केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने 10 अप्रैल 2021 को श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी में रोइंग अनुशासन के लिए खेले इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया।
- वर्तमान में, श्रीनगर में J&K स्पोर्ट्स काउंसिल वाटर स्पोर्ट्स अकादमी में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रोइंग के खेल डिसिप्लिन में ध्यान केंद्रित करेगा। उन्हें 145.16 लाख रुपये का पहली बार अनुदान और 96.17 लाख रुपये का वार्षिक आवर्ती अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- यह जम्मू और कश्मीर के दो केआईएससीई (KISCEs) में से एक है, जिसमें जम्मू में फैंसिंग अनुशासन के लिए मौलाना आज़ाद स्टेडियम है।
- वर्तमान में 23 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 24 KISCE हैं और उनमें से प्रत्येक ओलंपिक खेल अनुशासन पर केंद्रित है। यह भारत और ओलंपिक में उत्कृष्टता प्राप्त करने की बड़ी तस्वीर को ध्यान में रखते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विश्व स्तर तक के मौजूदा केंद्रों को स्केल करने का एक निरंतर प्रयास है।

3. ऑनलाइन विवाद समाधान

ACHIEVERS IAS ACA

- उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) में न्यायिक वितरण तंत्र को विकेंद्रीकृत, विविधता लाने, लोकतांत्रिक बनाने और विस्थापित करने की क्षमता है। वह NITI Aayog के साथ और जनता के लिए त्रिकोणीय, Dalberg, Dvara और NIPFP ICICI बैंक के सहयोग से, Agami और Omidyar India द्वारा विकसित ODR पर एक हैंडबुक की रिलीज़ इवेंट को संबोधित कर रहे थे।
- प्रतिरोध और भौतिक सुनवाई में वापस जाने की जिद के बावजूद महामारी के बाद, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने जोर दिया कि ओडीआर समय की जरूरत है!
- ओडीआर पुस्तिका में लिखा है कि भारत में पारंपरिक मुकदमेबाजी समय लेने वाली, महंगी और कीमती हो सकती है। यद्यपि न्यायपालिका इन मुद्दों को हल करने की दिशा में काम कर रही है, लेकिन ओडीआर इस स्थिति में मदद कर सकता है- उन विवादों के प्रकारों को सीमित करके जो अक्सर पहले स्थान पर अदालतों में आते हैं।
- ODR अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिए फायदेमंद हो सकता है, त्वरित और कुशल संकल्प की तलाश करने वाले व्यवसायों के लिए, और यहां तक कि उन व्यक्तियों के लिए जिनके लिए विवाद समाधान के पारंपरिक साधन बहुत अधिक और दुर्गम लगते हैं!
- NITI Aayog के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा, "ODR हैंडबुक कई योगदानकर्ताओं के सहयोगात्मक कार्य का परिणाम है। यह भारत में ODR को अपनाने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने और ODR को अपनाने की इच्छा रखने वाले व्यवसायों के लिए कार्रवाई योग्य प्रक्रियाओं को उजागर करने का इरादा रखता है।
- कोविद -19 ने अदालतों के समक्ष विवादों में तेजी की संभावना के साथ ओडीआर के लिए एक तत्काल आवश्यकता की मांग की है - विशेष रूप से उधार, ऋण, संपत्ति, वाणिज्य और खुदरा क्षेत्र में। उदाहरण के लिए, उदयन, भारत के व्यवसायों और दुकानदारों के लिए सबसे बड़ा बी 2 बी प्लेटफॉर्म है, जिसने ओडीआर प्रदाता प्रदाता का उपयोग करके एक महीने में 1800 से अधिक विवादों को हल किया है। प्रत्येक विवाद में औसतन 126 मिनट लगे। आने वाले महीनों में, ओडीआर एक ऐसा तंत्र हो सकता है जो व्यवसायों को शीघ्र समाधान प्राप्त करने में मदद करता है। ODR हैंडबुक व्यवसायों को ऐसा करने में सक्षम बनाता है।

4. लीलावती पुरस्कार 2020

- केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने नई दिल्ली में विजेताओं को महिला सशक्तिकरण पर AICTE लीलावती पुरस्कार 2020 प्रदान किया।
- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) ने लीलावती पुरस्कार की स्थापना की है।
- महिला सशक्तिकरण' विषय पर आधारित, AICTE ने कुल 456 प्रविष्टियों में से विजेताओं को अंतिम रूप दिया, जिन्होंने 6 उप विषयों में प्रतिस्पर्धा की, जिसमें महिला स्वास्थ्य, आत्मरक्षा, स्वच्छता और स्वच्छता, साक्षरता, महिला उद्यमिता, और कानूनी जागरूकता शामिल हैं।
- यह कार्यक्रम महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेगा और उन्हें शैक्षणिक संस्थानों में उच्च पदों पर आसीन करने में सक्षम करेगा।
- महत्वपूर्ण जानकारी:
- लीलावती पुरस्कार गणित में सार्वजनिक आउटरीच में उत्कृष्ट योगदान के लिए एक पुरस्कार है। इसका नाम 12 वीं शताब्दी के गणितीय ग्रंथ "लीलावती" के नाम पर रखा गया है जो भारतीय गणितज्ञ भास्कर II द्वारा लिखित अंकगणित और बीजगणित के लिए समर्पित है, जिसे भास्कर आचार्य के नाम से भी जाना जाता है। लेखक ने पुस्तक में, पद्य रूप में, एक लीलावती (शायद उनकी बेटी) में अंकगणित (प्रारंभिक) में समस्याओं की एक श्रृंखला और समाधान के लिए संकेत के साथ उनका पालन किया। यह काम मध्ययुगीन भारत में अंकगणित और बीजगणित सीखने का मुख्य स्रोत प्रतीत होता है।

5. ओडिशा की चिलिका झील में डॉल्फिन

- भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का में डॉल्फिन की आबादी और पिछले साल की तुलना में इस साल ओडिशा तट दोगुना हो गया है।
- राज्य के वन और पर्यावरण विभाग के वन्यजीव विंग ने इस साल जनवरी और फरवरी में आयोजित डॉल्फिन की जनगणना पर अंतिम आंकड़े जारी किए, जो संख्या में शानदार वृद्धि का संकेत देते हैं।
- 41 इकाइयों में विभाजित, वन्यजीव कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, वन विभाग के अधिकारियों, एनजीओ के सदस्यों, नाव ऑपरेटरों और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, मुंबई के शोधकर्ताओं ने आकलन अभ्यास में भाग लिया।
- जनगणना के दौरान तीन प्रजातियों को दर्ज किया गया था, इस साल 544 इरावदी, बोतल-नाक और कूबड़ वाली डॉल्फिन देखी गईं, जबकि पिछले साल यह 233 थी।
- वन्यजीव कार्यकर्ताओं को लुप्तप्राय इर्रावडी डॉल्फ़िन की आबादी में बड़ी वृद्धि के साथ जोड़ा जाता है, जो ज्यादातर चिलिका झील में पाए जाते हैं, जो इस वर्ष

ACHIEVERS IAS ACADEMY

2020 में 146 से 162 हो गई है। चिलिका के अलावा, राजनगर मैंग्रोव डिवीजन में 39 इरावाडी डॉल्फ़िन देखे गए, हालांकि 2020 में उनकी संख्या 60 से नीचे आ गई है।

- सबसे ज्यादा वृद्धि हम्पबैक डॉल्फिन के मामले में देखी गई है। 2020 में राजनगर मैंग्रोव में केवल दो हम्पबैक देखे गए। 2021 में, हालांकि, यह जनसंख्या खगोलीय रूप से बढ़कर 281 हो गई।
- "ये कूबड़ वाली डॉल्फ़िन किसी भी नदी प्रणालियों का हिस्सा नहीं थीं, इसलिए उन्हें आवासीय स्तनधारियों के रूप में पहचाना नहीं जा सकता। उन्हें ओडिशा तट के साथ यात्रा करते हुए देखा गया और अगली जनगणना में संख्या में उतार-चढ़ाव होने की संभावना है।
- बोतल-नाक डॉल्फ़िन की संख्या इस वर्ष 2020 में 23 से बढ़कर 54 हो गई।

- **<u>स्रोत</u>**

- चिल्का में इरावदी [डॉल्फिन] की आबादी में वृद्धि को अवैध मछली के खुलासे के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। हजारों हेक्टेयर चिलिका के पानी को अतिक्रमण मुक्त बनाने के बाद, इरावैडी डॉल्फ़िन को आवागमन के लिए अबाधित क्षेत्र मिला। इसके अलावा, पिछले साल COVID-19 लॉकडाउन के कारण, चिलिका झील पर तुलनात्मक रूप से कम पर्यटक नौकाएं थीं, जिससे डॉल्फिन को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए अनुकूल बना दिया गया था।

6. भारत की सबसे साफ नदी मानी जाने वाली उमंगोट !

- मेघालय के कम से कम 12 गाँवों के कठोर प्रतिरोध ने भारत की सबसे साफ नदी मानी जाने वाली उमंगोट पर 210 मेगावाट की पनबिजली परियोजना पर एक बाधा डाल दिया है।
- गाँव पूर्वी खासी हिल्स जिले में बांग्लादेश के साथ सीमा के पास हैं, लेकिन बांध पश्चिम जैंटिया हिल्स जिले के निकटवर्ती क्षेत्र में प्रस्तावित है।
- मेघालय ग्रामीण पर्यटन मंच के अध्यक्ष एलन वेस्ट खरकोंगोर ने कहा, "हर कोई मेगा-डैम परियोजना के खिलाफ है क्योंकि उनकी आजीविका नदी पर निर्भर है।"
- परियोजना के दस्तावेजों में कहा गया है कि अगर बांध टूट गया तो उमंगोट के किनारे बसे 13 गाँवों के लोगों के डूबने के कारण 296 हेक्टेयर ज़मीन खो सकती है।
- उमंगोट नदी कई पर्यटकों को बांग्लादेश की सीमा पर स्थित डावकी की ओर आकर्षित करती है। नदी का पानी इतना साफ है कि नावें नदी के तल पर अपनी छाया डालने के अलावा एक क्रिस्टल ग्लास की सतह पर आराम करती दिखती हैं।

7. भीख मांगना

- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चार राज्यों से कहा है कि वह भीख मांगने वाले अपराधों को निरस्त करने के लिए निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर तीन सप्ताह के भीतर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करें।
- जस्टिस अशोक भूषण और आर। सुभाष रेड्डी की खंडपीठ ने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा कि हालांकि इस साल 10 फरवरी को याचिका पर महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और बिहार को नोटिस जारी किया गया था, केवल बिहार ने अब तक अपनी प्रतिक्रिया दर्ज की थी ।
- मेरठ निवासी विशाल पाठक द्वारा दायर याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय के अगस्त 2018 के फैसले का उल्लेख किया गया है, जिसने राष्ट्रीय राजधानी में भीख मांगने को प्रतिबंधित कर दिया था और कहा कि बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट, 1959 के प्रावधान, जो भीख मांगना अपराध के रूप में संवैधानिक नहीं रह सकता है छानबीन
- भीख मांगने के कृत्य का अपराध करने वाले क़ानूनों के प्रावधान लोगों को एक अपराध करने या किसी को भूखा न रखने और अनुचित कार्य करने के बीच एक अनुचित विकल्प बनाने की स्थिति में डालते हैं, जो संविधान की बहुत ही भावना के खिलाफ जाता है और अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) का उल्लंघन करता है।
- जनगणना 2011 का हवाला देते हुए, दलील में कहा गया है कि भारत में भिखारियों की कुल संख्या 4,13,670 है और पिछली जनगणना से यह संख्या बढ़ी है।
- इसमें कहा गया है कि सरकार के पास सभी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और संविधान में राज्य नीति के निर्देशों के सिद्धांतों में अंतर्निहित सभी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने का जनादेश था।
- हालांकि, भिखारियों की उपस्थिति इस बात का सबूत है कि राज्य अपने सभी नागरिकों को ये बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में विफल रहा है, इस प्रकार इसकी विफलता पर काम करने और लोगों को भीख माँगने की जाँच करने के बजाय, भिखारी के कार्य का अपराधीकरण तर्कहीन है और दृष्टिकोण के खिलाफ है

- याचिका में बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट, 1959, पंजाब प्रिवेंशन ऑफ बेगारी एक्ट, 1971, हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट, 1971 और बिहार प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग को छोड़कर कुछ प्रावधानों को छोड़कर सभी प्रावधानों को "गैरकानूनी और शून्य" घोषित करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिनियम 1951।
- इसने देश के किसी भी हिस्से में प्रचलित अन्य सभी समान अधिनियमों को अवैध घोषित करने की भी मांग की है।

8. ईरान परमाणु कार्यक्रम

- ईरान ने घोषणा की कि उसने उन्नत यूरेनियम संवर्धन सेंट्रीफ्यूज शुरू किया है, जो कि संकट से निपटने के लिए वार्ता शुरू होने के कुछ दिनों बाद एक अशांत 2015 परमाणु समझौते के तहत उसके उपक्रमों के उल्लंघन में है।
- राष्ट्रपति हसन रूहानी ने राज्य टेलीविजन द्वारा प्रसारित एक समारोह में ईरान के नटांज़ यूरेनियम संवर्धन संयंत्र में 164 IR-6 सेंट्रीफ्यूज, 30 IR-5 और अन्य 30 IR-6 उपकरणों के तीन कैस्केड का उद्घाटन किया।
- यूरेनियम संवर्धन के लिए ईरान का नवीनतम कदम वियना में वार्ता के शुरुआती दौर के बाद शेष अमेरिका के प्रतिनिधियों के साथ परमाणु समझौते पर अमेरिका को वापस लाने पर है।
- पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प 2018 में इस सौदे से पीछे हट गए लेकिन उनके उत्तराधिकारी जो बिडेन ने कहा है कि वह वापसी के लिए तैयार हैं, यह तर्क देते हुए कि सौदा ईरान की परमाणु गतिविधियों को नाटकीय रूप से वापस लाने में सफल रहा है।
- वियना वार्ता न केवल ट्रम्प के आर्थिक प्रतिबंधों को उखाड़ फेंकने पर केंद्रित है, बल्कि अपनी खुद की कई प्रतिबद्धताओं को निलंबित करके जवाब देने के बाद ईरान को अनुपालन में वापस लाने पर भी है।
- ईरान ने मांग की है कि ट्रम्प द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंधों को संयुक्त राज्य अमेरिका पहले उठा ले, जिसमें इसके तेल निर्यात पर व्यापक एकतरफा प्रतिबंध शामिल है, इससे पहले कि वह निलंबित दायित्वों के अनुरूप वापस आ जाए।

9. सिंधु और गंगा नदी डॉल्फ़िन दो अलग-अलग प्रजातियां हैं!

- दक्षिण एशियाई नदी डॉल्फ़िन के विस्तृत विश्लेषण से पता चला है कि सिंधु और गंगा नदी डॉल्फ़िन एक नहीं, बल्कि दो अलग-अलग प्रजातियां हैं।
- वर्तमान में, उन्हें प्लेटानिस्टा गैंगेटिका के तहत दो उप-प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसके लिए एक संशोधन की आवश्यकता है। अध्ययन का अनुमान है कि सिंधु और गंगा नदी की डॉल्फ़िन लगभग 550,000 साल पहले गोताखोर हो सकती हैं।
- अंतरराष्ट्रीय टीम ने शरीर के विकास, खोपड़ी आकृति विज्ञान, दांतों की गिनती, रंग और आनुवांशिक श्रृंगार का अध्ययन किया और पिछले महीने के समुद्री स्तनपायी विज्ञान में निष्कर्ष प्रकाशित किए।
- पटना विश्वविद्यालय के लेखकों में से एक रवींद्र के। सिन्हा बताते हैं: "गंगा डॉल्फिन भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत एक शेड्यूल जानवर है, और इसे लुप्तप्राय: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर समझौते के अनुबंध - I में शामिल किया गया है प्रजाति (CITES), इसलिए आप भारत सरकार के सक्षम प्राधिकरण से CITES की अनुमति प्राप्त किए बिना किसी भी ऊतक या नमूने को विदेशी देशों में स्थानांतरित नहीं कर सकते। " एक और कारण यह था कि मृत जानवरों को ढूंढना असामान्य था क्योंकि वे या तो बहाव या डूबते हैं, और दुनिया भर में संग्रहालय संग्रह में केवल कुछ नमूने हैं और उनमें से अधिकांश क्षतिग्रस्त हैं।
- संरक्षण की स्थिति
- सिंधु और गंगा नदी की डॉल्फ़िन को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संगठन (IUCN) द्वारा लुप्तप्राय 'प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। डॉ। सिन्हा जो लगभग चार दशकों से गंगा डॉल्फ़िन का अध्ययन कर रहे हैं, बताते हैं कि नदी के पार बने बांध और बैराज जैसे भौतिक अवरोधों ने जीन प्रवाह को काफी हद तक कम कर दिया, जिससे यह प्रजाति कमजोर पड़ गई; उन्होंने कहा कि नदी का पानी भी बहुत तेजी से घट रहा है क्योंकि नदी के पानी को बैराज के माध्यम से निकाला जा रहा है और इससे डॉल्फिन के आवास प्रभावित हुए हैं। "पहले मछुआरे डॉल्फ़िन का शिकार करते थे और अपने तेल को चारा के रूप में इस्तेमाल करते थे, लेकिन हालांकि निर्देशित हत्या का अभ्यास बंद हो गया है और जानबूझकर शिकार नहीं किया जा रहा है क्योंकि वे आकस्मिक कैच के रूप में समाप्त होते हैं। इसके अलावा, 1990 के दशक से पहले, हमारे पास नौका और देश की नौकाएं थीं; लेकिन अब मशीनीकृत नावें भी डॉल्फ़िन की आकस्मिक चोट का कारण बन रही हैं।
- प्रदूषण के स्रोत

ACHIEVERS IAS ACADEMY

- गंगा एक्शन प्लान का एक हिस्सा होने के नाते, डॉ। सिन्हा ने नदी के एक बड़े हिस्से की निगरानी की और नोट किया कि प्रदूषण के बिंदु और गैर-बिंदु दोनों स्रोत डॉल्फ़िन के निवास स्थान को प्रभावित कर रहे हैं। "हाल ही में हमने चीनी नदी डॉल्फिन को विलुप्त होते देखा था। हालांकि भारत सरकार ने डॉल्फिन को कानूनी संरक्षण दिया है, लेकिन उन्हें बचाने में मदद करने के लिए स्थानीय समुदायों के साथ अधिक जमीनी कार्रवाई और करीबी काम करने की जरूरत है।

10. महात्मा ज्योतिबा फुले

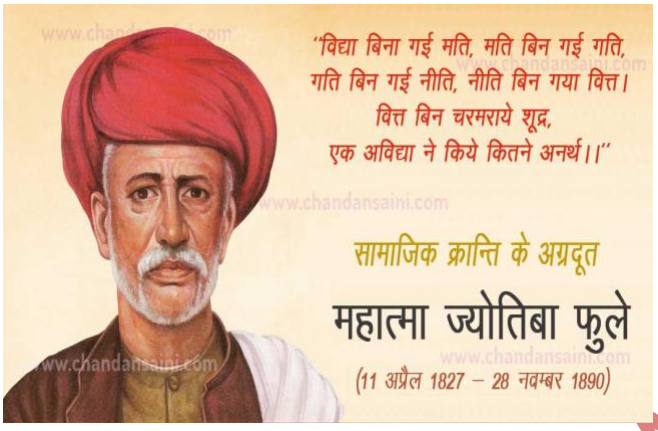

- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महान समाज सुधारक, विचारक, दार्शनिक और लेखक महात्मा ज्योतिबा फुले को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।
- जोतिराव गोविंदराव फुले (11 अप्रैल 1827 - 28 नवंबर 1890) एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, विचारक, जाति-विरोधी समाज सुधारक और महाराष्ट्र के लेखक थे।
- अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था के उन्मूलन और महिलाओं और शोषित जाति के लोगों को शिक्षित करने के उनके प्रयासों सहित कई क्षेत्रों में उनका काम आगे बढ़ा।वे और उनकी पत्नी, सावित्रीबाई फुले भारत में महिलाओं की शिक्षा के अग्रणी थे।
- फुले ने अपना पहला स्कूल लड़कियों के लिए 1848 में पुणे में तात्यासाहेब भिड़े के निवास स्थान या भिडेवाड़ा में शुरू किया।
- उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर शोषित जातियों के लोगों को समान अधिकार दिलाने के लिए सत्यशोधक समाज (सोसाइटी ऑफ ट्रुथ सीकर्स) का गठन किया।
- सभी धर्मों और जातियों के लोग इस संघ का हिस्सा बन सकते हैं जिन्होंने दलित वर्गों के उत्थान के लिए काम किया।
- फुले को महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार आंदोलन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। उन्हें 1888 में महाराष्ट्रीयन सामाजिक कार्यकर्ता विट्ठलराव कृष्णजी वांडेकर द्वारा सम्मानित महात्मा (संस्कृत: "महान-स्मरणीय", "आदरणीय") की उपाधि दी गई।

ACHIEVERS IAS ACADEMY